3

छत्तीसगढ़ सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ

5

संघर्ष से संभव हुआ पश्चिम बंगाल का उद्भव

7

एक ही मंदिर में लगातार तीसरी बार चोरी

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 11 प्रति सोमवार, 21 जुलाई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल, गृहमंत्री विजय शर्मा का डेढ़ वर्ष का कार्यकाल नाकामियों से भरा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यदि गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं तो जनता के बीच उनकी और पार्टी की बनेगी मजबूत छवि

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल को लेकर सवालों का सिलसिला तेज हो गया है। राज्य की कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आम लोगों में भय, असुरक्षा और शासन के प्रति गहरा अविश्वास पनप रहा है। आज छत्तीसगढ़ राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, उसका एक कारण है प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि आज अखबार की ज्यादातर खबरें क्राइम पर

आधारित ही दिखाई देती हैं। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की हालत के कारण गृहमंत्री विजय शर्मा हैं।

बीते डेढ़ वर्ष में बलात्कार, छेड़छाड़, लूटमार, चोरी और हिंसक अपराधों में भारी वृद्धि ने यह साबित कर दिया है कि गृहमंत्री राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने में बुरी तरह विफल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। यदि वे गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं तो जनता के बीच उनकी छवि मजबूत होगी। वहीं यदि चुप्पी साधे रहते हैं तो विपक्ष इसे उनके नेतृत्व की कमजोरी करार देगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार कब सख्त निर्णय लेगी। गृहमंत्री विजय शर्मा के लिए भी यह आखिरी मौका है कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और साबित करें कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। अन्यथा न केवल उनकी राजनीतिक साख दांव पर है बल्कि भाजपा सरकार की विश्वसनीयता भी।

आंकड़ों में बयां होती हकीकत

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विजय शर्मा के कार्यकाल में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले डेढ़ साल में राज्य में बलात्कार के 2682 मामले दर्ज किए गए, वहीं छेड़छाड़ की 5174 घटनाएं सामने आईं। लूट के मामलों में 38 प्रतिशत, डकैती में 44 प्रतिशत और चोरी की घटनाओं में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों ने विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के भीतर भी गृहमंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े करने का मौका दे दिया है।

(शेष पेज 6 पर)

पहली बारिश में ही ढह गई प्रदेश के विकास की नींव

पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच उलझी पड़ी हैं प्रदेश की लाखों किमी की सड़कें

-विजया पाठक

सड़कें सिर्फ कांक्रीट और डामर की परतें नहीं होतीं, ये किसी भी राज्य की विकास यात्रा की सबसे पहली सीढ़ी होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश में बारिश की पहली फुहार के साथ ही ये सीढ़ियाँ ढह जाती हैं और साथ ही ढह जाता है आमजन का विश्वास। प्रशासन, नीतियों और विकास के खोखले वादों पर राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर तक हर शहर में बरसात के पहले दौर में ही सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है। गड्ढे, जलभराव, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं अब सामान्य हो गई हैं, जैसे ये सरकार द्वारा स्वीकृत मानक प्रक्रिया का हिस्सा हों। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों का हाल कब तक देखने को मिलेगा। कब तक प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह अफसरों को सिर्फ कमरे से बैठकर सड़क ठीक करने की हिदायत देते रहेंगे।

(शेष पेज 2 पर)

बदहाल सड़कें और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बेतुका बयान

हिमांशु गुप्ता का डीजी पदोन्नति पर उठ रहे सवाल

ऐसे विवादास्पद अधिकारी को अहम जिम्मेदारी देना नुकसानदायक

-विजया पाठक

1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता के डीजी पदोन्नति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीपीसी के लिए हिमांशु गुप्ता समेत कई अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक यूपीएससी को भ्रामक एवं गलत जानकारी भेजी है। उक्त नियम विरुद्ध पदोन्नति के लेकर अब कार्रवाही की मांग की जा रही है। जबकि नियमानुसार डीजी के पद पर पदोन्नति 1994 बैच के आईपीएस एसआरपी कल्लूरी की होनी थी जिन्होंने अपने सर्विस काल की 30 सालों की मियाद पूरी कर ली है।

हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस है लेकिन जब मध्यप्रदेश में 1995 में वरिष्ठता सूची जारी की गई उसमें हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल नहीं है।

(शेष पेज 2 पर)

1995 की वरिष्ठता सूची में हिमांशु गुप्ता का नाम नहीं

पहली बारिश में ही ढह गई प्रदेश के विकास की नींव

(पेज 1 का शेष)

कड़वी सच्चाई करोड़ों में निर्माण, लाखों में मरम्मत

सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि मध्यप्रदेश में हर साल सड़कों के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं। भोपाल में ही पीडब्ल्यूडी के पास 573 किमी सड़कों का रखरखाव है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनमें से 3 प्रतिशत सड़कें बारिश की पहली बूँद में ही गड्ढों में तब्दील हो गईं। यही हाल दूसरे महानगरों का भी है। फिर इन सड़कों की मरम्मत पर लाखों रुपये फिर से खर्च होते हैं। यानि एक ही सड़क बार-बार बने, टूटे और फिर से बने। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन सवाल वही रहता है।

क्यों खराब हो जाती हैं राज्य सरकार द्वारा निर्मित सड़कें?

सड़कों की बदहाली का कारण सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण 'विफल व्यवस्था' है। मानक विहीन निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता अक्सर संदेह के घेरे में रहती है। बिटुमिन की जगह पतला टार, रेत की जगह धूल और मजबूती की जगह 'जुगाड़' प्राथमिकता पाते हैं। भ्रष्टाचार और कमीशन ठेकेदारों को भुगतान से पहले ही 'सांठगांठ का हिस्सा' तय हो जाता है। कहा जाता है कि एक सड़क पर 10 करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन असल में 05 करोड़ भी निर्माण में नहीं लगते। ड्रेनेज सिस्टम का अभाव सड़क बनें, लेकिन बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था न हो, तो गड्ढे और क्षरण तय हैं। जवाबदेही का अभाव निर्माण एजेंसी, इंजीनियर, निरीक्षक और मंत्री- कोई भी खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। गड्ढा दिखा तो शिकायत ऐप पर दर्ज कर दो, समाधान की उम्मीद करना बेकार है।

पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच सड़कों की जिम्मेदारी का अंधा खेल

राज्य की सड़कों के अधिग्रहण को लेकर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच वर्षों से खींचतान जारी है। एक विभाग कहता है कि सड़क हमारी नहीं, दूसरे पर आरोप मढ़ देता है। उदाहरण के लिए, भोपाल की 27 जर्जर सड़कों में से 18 को लेकर दोनों विभागों में पत्राचार चलता रहा, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। जब जिम्मेदारी तय ही नहीं होगी, तो सुधार कैसे होगा? यह वही स्थिति है जैसे घर में आग लगी हो और परिवार के दो सदस्य यह तय न कर पा रहे हों कि बाल्टी कौन लाएगा।

करोड़ों खर्च, लेकिन सही नतीजे नहीं मिल रहे

प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण और रख-रखाव में हर सत्र लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए। 1700 करोड़ रूपये का बजट शहरी निकायों को जारी है। बारिश से पहले प्रतीक्षा में रुका यह बजट, लेकिन फंड के बावजूद मरम्मत संचालन धीमा। 1100 करोड़ की फोरलेन पर पहली बारिश में टूटी। बालाघाट–गोंदिया हाईवे का निर्माणाधीन फोरलेन बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि अगर छह महीने में सड़क गड्ढा हो जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए।

नेशनल हाईवे पर क्यों नहीं आते गड्ढे?

आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बारसात में भी नेशनल हाईवे पर यह हाल नहीं देखने को मिलता। इसका मुख्य कारण है बेहतर निर्माण मानक, सख्त अनुबंध और निगरानी, भुगतान में गुणवत्ता के आधार पर कटौती, जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट प्रणाली।

क्या सिर्फ बैठकों से ठीक हो जाएंगी सड़कें?

पीडब्ल्यूडी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अक्सर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर समीक्षा, बैठकें करते हैं। वहाँ स्लाइड शो चलाए जाते हैं, डिजिटल नक्शे दिखाए जाते हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि "सड़कें गड्ढामुक्त होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में, न मंत्री मौके पर जाते हैं, न अफसरों को जमीनी हकीकत का अंदाजा होता है। बैठकें दिखावे की रस्म बन चुकी हैं, जिनका आमजन के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता।

टोल टैक्स का बोझ, लेकिन सुविधाओं में शून्यता

प्रदेश में टोल टैक्स वसूली जोर-शोर से की जाती है। हर 20-30 किमी पर एक टोल प्लाजा खड़ा है, जो वाहन चालकों से मोटी रकम वसूल करता है। लेकिन बदले में सड़कें टूटी हुई, न तो रैनबसेरा, न आपातकालीन सेवा, अंधेरे में लाइटें नहीं, बारिश में जलभराव जैसी स्थिति बनती है। बड़ा सवाल यह है कि जब सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले ठेकेदार तय होता है और अक्सर यह प्रक्रिया 'कागजी योग्यता' से ज्यादा 'पहुंच' पर निर्भर करती है। ठेका मिलते ही सबसे पहले 'कमीशन सेटिंग' होती है। विभागीय इंजीनियर, अफसर और नेतागण अपना हिस्सा पहले ही मांग लेते हैं। निर्माण में जो बजट बचता है, उसमें सड़क बनती है।

हिमांशु गुप्ता का डीजी पदोन्नति पर उठ रहे सवाल

(पेज 1 का शेष)

जबकि 1995 की वरिष्ठता सूची में गुरजिंदर पाल सिंह और कल्लूरी का नाम शामिल हैं। इस प्रकार हिमांशु जब भी वरिष्ठता सूची में आएंगे तो शिवराम प्रसाद के नीचे ही आएंगे। इनकी पहुंच और जुगाड़ का यह आलम है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को भी इन्होंने ठेंगा दिखाया और अपनी वरिष्ठ को गलत तरीके से कायम रखवाने में सफल रहे। मसला दरअसल यह है कि हिमांशु गुप्ता त्रिपुरा कैडर के आईपीएस हैं। इसके बाद कैडर ट्रांसफर योजनांतर्गत हिमांशु गुप्ता की स्वयं की मांग पर उन्हें मध्यप्रदेश कैडर आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तब इन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया। हिमांशु गुप्ता कैडर ट्रांसफर अंतर्गत मध्यप्रदेश भारतीय पुलिस सेवा की सूची में सम्मलित हैं। नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा का जो अफसर कैडर ट्रांसफर के अंतर्गत किसी राज्य में स्थानांतरित होता है तो उसका नाम उस राज्य के पदक्रम सूची में वरिष्ठता कम में अपने बैच में अंतिम स्थान पर प्रक्टिप किया जाता है। इसलिए कहना गलत नही है कि वरिष्ठता क्रम और डीओपीटी के नियम अनुसार एसआरपी कल्लूरी का नाम डीजी पद के लिए दर्ज किया जाना था।

पदोन्नति समिति को किया गुमराह

हिमांशु गुप्ता द्वारा गृह विभाग के चंद अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अनियमित पदोन्नति प्राप्त की है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली को अपनी पदोन्नति के सम्बंध में गलत एवं भ्रामक जानकारी भेजी गई। उक्त मामले में तथ्य यह है कि केंद्रीय न्यायिक अभिकरण द्वारा दिनांक 30.04.2024 को 1994 बैच के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) के अनिवार्य सेवा निर्वित आदेश को अपास्त करते हुए समस्त परिणामी लाभ सहित सेवा में वापस लेने के आदेश दिया गया था। जिसे राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इसके बाद जून 2024 के अंतिम सप्ताह में जब डीजी के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्रवाही की गई। तब माननीय न्यायालय के आदेश परिपालन में नियमानुसार जीपी सिंह के पदोन्नति हेतु लिफाफा सील कर डीजी का एक पद आरक्षित रखना चाहिए था। चूंकि जीपी सिंह वरिष्ठता क्रम में हिमांशु से ऊपर हैं। हिमांशु गुप्ता द्वारा गृह विभाग के अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव से मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक विभागीय पदोन्नति समिति को गुमराह किया गया। वहीं सविता खंडेलवाल आत्महत्या मामले में भी हिमांशु गुप्ता संदेह के घेरे में हैं।

सविता के पति अखिलेश खंडेलवाल ने हिमांशु गुप्ता पर कई तरह के आरोप लगाये थे।

अधिकारी राज में कुछ भी संभव

माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश के परिपालन में जीपी सिंह द्वारा 20.12.2024 को समस्त परिणामी लाभ सहित अपनी सेवा में उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के सेवानिवृत्ति के बाद 5.2.2025 को डीजी का एक पद रिक्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन हेतु फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में रिव्यू डीपीसी की मीटिंग आयोजित की गई। उक्त बैठक में नियमानुसार जीपी सिंह की पदोन्नति 2.7.2024 से जिस पद को आरक्षित रखा जाना था, उसमें 5.2.2025 को हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति की अनुशंसा की गई। वही जब स्लेक्ट सेवा आयोग पुनः प्रस्ताव भेजा गया तब षड्यंत्रपूर्वक पदोन्नति 2.7.2024 दिखाई गई। अब इसमें गृह विभाग से चंद अधिकारियों की मिलीभगत से 2.7.2024 डीजी पद निर्माण की जुगत केबिनेट में लगाई गई थी, जो नियमतः तो संभव नही हो सकती थी। लेकिन जंगल राज के अधिकारी शासन में कुछ भी असंभव नही है। उपरोक्त सारे तथ्यों को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति नियम विरुद्ध ही नही षड्यंत्रपूर्वक अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। हिमांशु गुप्ता द्वारा डीजी के पैनल हेतु प्रस्ताव में पदोन्नति दिनांक रिव्यू डीपीसी के अनुशंसा के विपरीत दर्ज कराई गई। जबकि वास्तव में दिनांक 5.2.2025 को डीजी के रिक्त पद पर कल्लूरी को पदोन्नत किया जाना चाहिए था न कि हिमांशु गुप्ता को।

25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर कांग्रेस नेताओं की जान ले ली थी। उस समय बस्तर आईजी हिमांशु गुप्ता थे। तब हिमांशु गुप्ता को पुलिस मुख्यालय रायपुर बुला लिया गया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था। जबकि उस दिन मयंक श्रीवास्तव छुट्टी पर थे और उनकी कोई गलती नही थी। यहां सवाल उठता है कि जब एसपी को निलंबित किया गया लेकिन हिमांशु गुप्ता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस समय हिमांशु गुप्ता की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। कहा गया था कि हमले से समय करीब 300 नक्सली थे और इनका क्षेत्र में कई दिनों से मूवमेंट था। फिर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी।

'पीके का फंडा' की पहली प्रति राज्यपाल को भेंट

प्रवीण कक्कड़ ने माँ की स्मृति को किया समर्पित

प्रख्यात सामाजिक चिंतक, लेखक और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ ने अपनी नई चिंतनपरक कृति "पीके का फंडा" की प्रथम प्रति आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल, माननीय श्री मंगूभाई पटेल को राजभवन में सादर भेंट की। यह अवसर केवल एक पुस्तक भेंट नहीं, बल्कि प्रेरणा, श्रद्धा और सार्थक विचारों के संगम का साक्षी बना। कक्कड़ ने इस दिन को अपने जीवन का एक अत्यंत भावपूर्ण क्षण बताया, क्योंकि 16 जुलाई उनकी पूज्यनीय माता, स्व. श्रीमती विद्यादेवी कक्कड़ जी की जयंती भी है। उन्होंने भावुकता से कहा, "यह पुस्तक मैंने माँ की पावन स्मृति को समर्पित की है। जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया, उसमें उनकी प्रेरणा, संस्कारों और मूल्यों की गहरी छाया है।" यह समर्पण पुस्तक के मूल भाव—आत्मिक जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन—से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

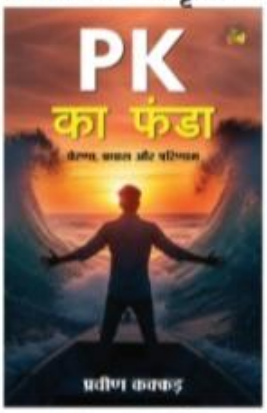

शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह कृति प्रवीण कक्कड़ के प्रशासनिक, सामाजिक और निजी अनुभवों का ऐसा समावेश है, जो पाठकों को न केवल प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें आत्ममंथन की दिशा में ले जाती है- यह स्पष्ट करते हुए कि वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है, न कि बाहरी परिवेश से। माननीय राज्यपाल महोदय को पुस्तक भेंट करने के इस विशेष अवसर पर प्रवीण कक्कड़ के सुपुत्र सलिल कक्कड़, तथा "पीके का फंडा" टीम से सुमित अवस्थी और प्रकृति चटर्जी भी उपस्थित रहे। शिवना प्रकाशन प्रमुख पंकज सुबीर ने एक प्रेरक और चिंतनपरक कृति बताया। उन्होंने कहा, "यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन की आपाधापी में कुछ पल ठहरकर, भीतर झाँकने और स्वयं से संवाद करने का हार्दिक निमंत्रण है।" शिवना प्रकाशन के संपादक शहरयार ख़ान ने बताया कि "पीके का फंडा" ने अपनी रिलीज़ से पहले ही पाठकों के बीच असाधारण लोकप्रियता प्राप्त की है। अमेज़न की प्री-बुकिंग बेस्टसेलर रैंकिंग में यह पुस्तक पहले स्थान पर रही, और अब तक 1000 से अधिक प्रतियाँ ऑनलाइन प्री-बुक हो चुकी हैं। यह उपलब्धि लेखक की विचारशील लेखनी और पाठकों के अटूट विश्वास का प्रमाण है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रवीण कक्कड़ की पहली पुस्तक "दंड से न्याय तक" को अंतरराष्ट्रीय "शिवनाकृति सम्मान" प्राप्त हो चुका है।

राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर रही हैः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के युवाओं में तीरंदाजी का प्राकृतिक कौशल है। इस प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु रायपुर एवं जशपुर में एनटीपीसी के सहयोग से 60 करोड़ रुपये की लागत से आर्चरी अकादमी की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब आकाश को छूएंगी। राज्य के खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर से ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दक्ष बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी एवं स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक रुचि एवं नैसर्गिक प्रतिभा है, विशेषकर आदिवासी अंचलों के युवाओं में अत्यधिक संभावनाएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बिंद्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने में ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चर्चा के दौरान बिंद्रा ने बताया कि वे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए विविध कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि फाउंडेशन द्वारा खेलरित में संचालित ये कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की। मुख्यमंत्री साय को बिंद्रा ने अवगत कराया कि स्पोर्ट्स इंजरी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी, पुनर्वास एवं उपचार उपरांत देखभाल की संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्वस्थ होकर पुनः खेल क्षेत्र में सक्रीय हो सकें। इस हेतु फाउंडेशन के साथ देश के 30 उत्कृष्ट चिकित्सकों का नेटवर्क कार्यरत है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदमः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है, जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी-मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी में शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विधेयक को विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर, छत्तीसगढ़ अब मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है, जिसने जनविश्वास विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में रोजगार व्यवसाय को आसान बनाने के साथ-साथ गैर अपराधिक श्रेणी के मामलों में व्यापारियों एवं आम नागरिकों न्यायालयीन मुकदमे से संरक्षित करना और एक सुगम व्यावसायिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण वातावरण तैयार करना है।

यह विधेयक दंड देने के बजाय व्यवसाय को दिशा देने और ऐसी नीति बनाने में सहायक है, जो व्यावहारिक और संवेदनशील हों। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने (शास्ति) के दायरे में लाता है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और अदालतों पर बोझ कम होगा, साथ ही नागरिकों को छोटी गलतियों के लिए आपराधिक मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस विधेयक में छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, और छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसायटी अधिनियम से संबंधित 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। विधेयक का लक्ष्य उद्यमियों को नियामकीय सूचनाओं से संबंधित देरी के लिए आपराधिक मुकदमे के डर से मुक्ति दिलाना है। अब ऐसे मामलों में केवल प्रशासकीय जुर्माना लगेगा, जिससे व्यापार व्यवसाय में आसानी होगी। विधेयक में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब के उपभोग के मामले में पहली बार सिर्फ जुर्माना और इसकी पुनरावृत्ति के मामले में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पत्रकार और संस्कृतिकर्मी राजकुमार सोनी बने जसम के राष्ट्रीय सह-सचिव

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। झारखंड की राजधानी रॉची में जन संस्कृति मंच के दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश के नामचीन रंगकर्मी जहूर आलम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वहीं तीसरी बार राष्ट्रीय महा सचिव की जिम्मेदारी मनोज सिंह को सौंपी गई है। सम्मेलन में इस बार छत्तीसगढ़ की इकाइयों को उसकी सक्रियता के चलते महत्वपूर्ण जगह दी गई है। पत्रकार और संस्कृतिकर्मी राजकुमार सोनी को जन संस्कृति मंच की राष्ट्रीय इकाई में सह-सचिव नियुक्त किया गया जबकि राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में कई प्रतिबद्ध लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में आलोचक सियाराम शर्मा कथाकार कैलाश बनवासी, रूपेंद्र तिवारी, दीपक सिंह, कामिनी त्रिपाठी और बिलासपुर जसम के अध्यक्ष मुदित मिश्रा को शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय परिषद में सुरेश चाहने, घनश्याम त्रिपाठी, सुलेमान खान, एन पापा राव, अशोक तिवारी, आलिम नकवी, शायर सुखनवर, वंदना कुमार, इंद्र कुमार राठौर, समीर दीवान, अजय शुक्ला, कमलेश पांडे, अब्दुल रज्जाक, निहाल और आदित्य को शामिल किया गया है। अभी चंद दिनों पहले मध्यप्रदेश के अशोक नगर में जन संस्कृति मंच की इकाई गठित की गई। अशोक नगर के कवि हरगोविंद पुरी को भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है। सम्मेलन में इस बार बड़ी संख्या में लेखकों और संस्कृति कर्मियों ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की और फ़ासीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के ख़िलाफ़ अपने विचार रखें। सम्मेलन में दो दिन सांस्कृतिक सत्र का आयोजन भी किया गया।

सम्पादकीय

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का नया सूर्योदय

भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है –डॉ. शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने हाल ही में अपनी सफल अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से न केवल भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ। बचपन से ही उन्हें सितारों और ग्रहों को देखने की गहरी जिज्ञासा थी। उनके पिता सरकारी कर्मचारी तथा माता शिक्षिका थीं। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के एक सरकारी विद्यालय से पूरी करने के बाद शुभांशु ने आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने इसरो से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया और नासा के लिए भी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में सेवाएं दीं। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रॉकेट प्रणोदन और अंतरिक्ष यात्री जीवन समर्थन प्रणालियों पर गहन शोध किया। उनका शोधपत्र 'इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम फॉर ह्यूमन स्पेसफ्लाइट' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 2016 में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से जुड़े और गगनयान मानव मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बने। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लंबे समय से प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा के बाद इसरो ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तकनीकी कौशल ने उन्हें इस मिशन का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाया।

रूस में उन्होंने अंतरिक्ष उड़ान, शून्य गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष यान से बाहर जाने की आपातकालीन ट्रेनिंग, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष चिकित्सा, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्पेससूट्स, और सिमुलेशन का गहन अभ्यास किया। उनकी ट्रेनिंग में एयरोबिक, एनेरोबिक, तैराकी, पर्वतारोहण तथा वर्चुअल स्पेस मिशन जैसे अनेक चरण शामिल थे।

2025 में जब गगनयान मानव मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से हुआ, तो डॉ. शुभांशु शुक्ला प्रमुख पायलट वैज्ञानिक के रूप में इस यात्रा में शामिल हुए। यह मिशन लगभग 7 दिनों का था, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में प्रयोग किए।

इस मिशन के दौरान शुभांशु ने मानव शरीर पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव, अंतरिक्ष भोजन की प्रभावशीलता तथा यान के भीतर ऑक्सीजन, तापमान और दबाव नियंत्रण प्रणालियों की जांच संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय जीवन समर्थन प्रणाली (Indian Life Support System) का भी परीक्षण किया, जिसे इसरो ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया था। सात दिनों के बाद जब गगनयान समुद्र में उतरा, तो यह क्षण भारत के लिए ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री सहित पूरे देश ने उनका स्वागत किया। इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया, जिनके पास मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। इस यात्रा से भारत को भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं। इनमें जीवन रक्षक प्रणाली की कार्यक्षमता, अंतरिक्ष में भारतीय खाद्य पदार्थों की उपयोगिता, अंतरिक्ष यात्री के मानसिक स्वास्थ्य पर शून्य गुरुत्व का प्रभाव तथा अंतरिक्ष चिकित्सा के कई पक्ष शामिल हैं। इन प्रयोगों के आधार पर भारत दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा, चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकता है। डॉ. शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर है। उन्होंने साबित किया कि स्वप्न देखने का साहस, निरंतर परिश्रम और अनुशासन हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उनकी सफलता ने भारत को नयी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा लेंगी और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में विश्वगुरु बनाने के संकल्प को साकार करेंगी।

सियासी गहमागहमी

कभी भी लग सकती है भूपेश बघेल को हथकड़ी

कहते हैं राजनीति में हाथ मिलाने की बड़ी परंपरा है, लेकिन यहां तो अब हाथ मिलाने से ज्यादा हाथ पकड़ने और हथकड़ी लगाने का जमाना चल पड़ा है। भूपेश बघेल पर भी कभी भी हथकड़ियां लग सकती हैं ये खबर सुनते ही पाटी कार्यकर्ता सोच में पड़ गए कि आखिर पांच पकड़ें या जमानत की तैयारी करें। वैसे भी, देश में इन दिनों सियासत हथकड़ियों की ही धुरी पर घूम रही है। कोई घोटाला, कोई जांच, कोई ईडी, सीबीआई और फिर टीवी पर चमचमाती स्टील की हथकड़ी– यही आजकल नेताओं की नई पहचान है। भूपेश बघेल को भी पता है कि राजनीति में मुख्यमंत्री कुर्सी के साथ 'हथकड़ी का माप' भी मुफ्त आता है। कल तक जो विरोधियों की गिरफ्तारी पर टीवी डिबेट में भाषण दे रहे थे, आज उन्हीं को डर सता रहा है कि कहीं खुद की कलाई की नाप तो नहीं ली जा रही। वैसे हथकड़ी भी सोचती होगी, किस-किस का भार उठाऊं। नेताओं का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता और पुलिस की हथकड़ी का आराम। भूपेश बघेल पर हथकड़ी लगे या न लगे, लेकिन राजनीति में यह लाइन हमेशा सच रहेगी- कुर्सी चाहे कितनी भी ऊंची हो, हाथ हमेशा हथकड़ी की पहुंच में रहते हैं।

मंत्रालय में गर्म हुई मुख्य सचिव पद की सियासत

मध्यप्रदेश के मंत्रालय में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है कौन बनेगा मुख्य सचिव? अनुराग जैन के बाद नये मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, हर कोई अपनी-अपनी जोड़तोड़ में जुटा है। कोई दिल्ली दरबार के दरवाजे खटखटा रहा है तो कोई मुख्यमंत्री निवास की परिक्रमा कर रहा। मुख्य सचिव पद को लेकर हमेशा से रस्साकशी रही है, क्योंकि यह कुर्सी सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं करती बल्कि पूरे शासन की दिशा तय करती है। ऐसे में वरिष्ठतम अफसर, मजबूत राजनीतिक पकड़, संघ की पसंद, मुख्यमंत्री की टीम और दिल्ली की सहमति– इन सभी समीकरणों का मेल जरूरी होता है। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठता सूची में ऊपर बैठे कई अधिकारियों की धड़कनें तेज हैं, वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जिनका नाम चर्चा में जरूर है लेकिन उनकी कार्यशैली और सॉफ्ट स्किल को लेकर सत्ता में संदेह बना हुआ है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

बिहार में चुनाव आयोग 'SIR' के नाम पर खुले हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया।
काम सिर्फ चोरी, नाम 'SIR' - पर्दाफाश करने वाले पर लगेगी FIR!
EC अब भी 'Election Commission' है या पूरी तरह BJP की 'Election Chori' शाखा बन चुका है?
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में पहले से ही नौकरियों का अकाल है और सरकारी भर्ती निकलती भी है तो उसमें हजारों योग्य लोग सरकार की लालफीताशाही और मनमानी की भेंट चढ़ जाते हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक वर्ग तीन भर्ती की प्रक्रिया में नियमों में जो बदलाव किया है, वह अत्यंत अन्यायपूर्ण है।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

ममता बनर्जी के संघर्ष, जन नेतृत्व से संभव हुआ पश्चिम बंगाल का उद्भव

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारत की राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसी महिला नेता हैं, जिन्होंने संघर्ष, साहस और अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता से नया इतिहास रचा। 'दीदी' के नाम से प्रसिद्ध ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में हुआ। ममता का जीवन अत्यंत साधारण परिवार में बीता, लेकिन उनके भीतर नेतृत्व क्षमता बचपन से ही थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक इतिहास में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून तथा शिक्षा (B.Ed.) की भी पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही वह सामाजिक मुद्दों के प्रति मुखर रहीं। उनके पिता का निधन तब हुआ, जब वह मात्र 17 वर्ष की थीं। इसके बाद उन्होंने परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी निभाई और शिक्षा को जारी रखा।

1970 के दशक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1976 में उन्होंने कांग्रेस की महिला शाखा 'महिला कांग्रेस' की महासचिव का पद संभाला। उनके जीवन का पहला बड़ा राजनीतिक पड़ाव 1984 में आया, जब उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और CPI (M) के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को पराजित किया। वह उस समय की सबसे युवा सांसद बनीं। 1984 से 1989 तक सांसद रहने के बाद वह 1991 में पुनः लोकसभा पहुंचीं। इसके बाद नरसिंह राव सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास, युवा कल्याण, खेल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। अपने मुखर स्वभाव और बेबाकी के कारण वह केंद्र सरकार में अलग पहचान बनाने लगीं। 1997 में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उनकी पार्टी ने बंगाल में कांग्रेस के विकल्प के रूप में जगह बनाना शुरू किया। 1997 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के साथ ही उन्होंने वामदलों के 34 वर्षों के शासन को चुनौती देना शुरू किया। जनता के मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष धीरे-धीरे व्यापक होने लगा। 1999 में वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेलवे मंत्री बनीं और रेलवे के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। 2002 में वह कोयला और खनिज मंत्री भी रहीं।

2006-2007 का समय ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने सिंगूर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा। इसके बाद नंदीग्राम में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में उन्होंने व्यापक जनांदोलन का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी जननेता बना दिया। गरीब, किसान और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई ने उन्हें 'दीदी' की छवि दी। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से वामपंथी मोर्चे को सत्ता से बाहर कर दिया। 34 वर्षों का वाम शासन खत्म कर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, कन्याश्री योजना, सबुज साथी (साइकिल वितरण) और शहरी विकास के क्षेत्र में कई नई योजनाएं लागू कीं। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की और अपनी लोकप्रियता को कायम रखा।

राजनीति के अलावा ममता बनर्जी एक कवयित्री और चित्रकार भी हैं। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं तथा उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां भी लग चुकी हैं। उन्होंने बांग्ला में कई किताबें लिखी जिनमें उनके राजनीतिक अनुभव और सामाजिक दृष्टिकोण झलकते हैं। उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप भी लगे। लेकिन उनकी व्यक्तिगत सादगी, सादे कपड़े, हवाई चप्पल और हर वर्ग के बीच सहज पहुंच ने उन्हें आलोचनाओं से परे भी रखा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने के संकेत दिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में वह बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी छवि एक ऐसी महिला नेता की है, जो सत्ता के किसी भी शिखर से टकरा सकती हैं।

ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में यह संदेश दिया कि साधारण परिवार की महिला भी दृढ़ इच्छाशक्ति से इतिहास बदल सकती है। उनकी राजनीति किसानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों के लिए केंद्रित रही है। ममता बनर्जी आज भी संघर्ष की प्रतीक हैं और आने वाले वर्षों में उनकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णायक हो सकती है।

हरदा में करणी सेना पर पुलिस का हमला

दिग्विजय सिंह ने दिखाई तत्परता- सरकार को कठघरे में खड़ा किया, विपक्ष का नहीं मिला साथ, जीतू पटवारी की काबिलियत पर उठ रहे सवाल

-विजया पाठक

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसे बर्बर कार्रवाई करार देते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की "सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश" बताया है। पुलिस ने करणी सेना पर जो सख्ती दिखाई है उससे पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतर आयी। प्रदर्शन और नारेबाजी पर सरकार-पुलिस प्रशासन का विरोध जताया। पुलिस ने करणी सेना पर बर्बरता दिखाते हुए पानी की बौछारें मारी, आंसू गैस के गोले दागे और लाठियों की बरसाई। जिससे दर्जनों लोग घायल हुए। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया। हालांकि करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर को सशर्त रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई गुपचुप तरीके से हुई है। लेकिन 54 लोग सुनील सिंह के साथ अभी भी जेल में हैं।

क्या है मामला?

करणी सेना के प्रदर्शनकारी पैसे लेकर आरोपी को बचाने का आरोप लगाकर थाने का घेराव करने पहुंचे थे। आरोप था कि पुलिस ने एक ठगी के मामले में पैसा लेकर आरोपी को बचाया है। इसी सिलसिले में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और लाठियां चलाई। पुलिस ने इस मामले में करणी सेना जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सुनील राजपूत ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने ठगी के मामले में ढाई लाख रुपए लेकर आरोपी को बचाया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले को नही दिया तूल

हरदा में करणी सेना पर हुए हमले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ज्यादा तूल नही दिया। सिर्फ बयानबाजी पर मामले को शांत कर दिया। जबकि यह बहुत बड़ा मुददा था। पुलिस प्रशासन की बर्बरता और हिंसा को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यहां पर जीतू पटवारी की काबिलियत और मंशा पर भी प्रश्नचिंह लगता है। प्रदेश के एक सक्रिय संगठन पर हमला हो जाता है और सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया जाता है लेकिन मजबूत विपक्ष सिर्फ तमाशबीन बनकर देखता रहता है। यह विपक्ष की विफलता है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को अनैतिक मुददों पर घेरना होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नही हो रहा है। करणी सेना पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है पर प्रदेश का विपक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में केवल तमाशा देख रहा है।

क्या है करणी सेना?

करणी सेना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से इसे लुभाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में राजपूत बहुल वाले इलाकों में इसका प्रभाव देखा जाता है। मार्च 2023 में संगठन के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद भी यह संगठन सक्रिय बना हुआ है और विभिन्न राज्यों में इसका विस्तार जारी है। करणी सेना तब सबसे अधिक चर्चा में आई जब 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के विरोध में इसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। करणी सेना को एक साहसी और निडर संगठन माना जाता है। हिंदी भाषी राज्यों में इस संगठन का काफी प्रभाव है। जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानता है।

दिग्विजय सिंह ने दिखाई तत्परता, सरकार को कठघरे में खड़ा किया

हरदा में पुलिस और करणी सेना के बीच हुए विवाद पर दिग्विजय सिंह ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने एसपी और कलेक्टर का ट्रांसफर कराने की मांग की है। बीजेपी की राजपूत लॉबी इस मामले में समाज का समर्थन कर रही है। हरदा में राजपूत समाज और पुलिस के आमने-सामने आने के मामले के बाद यहां पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक बड़े व्यापारी को बचाने के लिए ऐसे लोगों को टारगेट किया, जिनका कोई अपराध नहीं था। क्या एक जगह जमा होना अपराध है? यही नहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जाति और नाम पूछकर लोगों को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि राजपूत समाज के लोगों के वाहनों के साथ तोड़फोड़ की।

हरदा में करणी सेना के साथ जो कुछ हुआ है यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि हक की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हरदा में तो यही हुआ। वहीं बात विपक्ष की बात करें तो वह बिल्कुल विपक्ष की भूमिका को निष्क्रिय माना जा सकता है। तमाम नेता केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। केवल दिग्विजय सिंह ने मामले को जगह-जगह जाकर उठाया। यहां कांग्रेस की बड़ी चूक हो रही है। कांग्रेस चाहती तो इस मामले को बड़े स्तर पर उठा सकती थी। खासकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई। इसी जगह पर बीजेपी होती तो पूरे प्रदेश में हल्ला मचा देती और सरकार को मुसीबत में डाल देती। लेकिन लगता है कि जीतू पटवारी बीजेपी के पैरलर चल रहे हैं और सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। प्रदेश में और भी कई मुददे आये हैं जब भी यही देखा गया है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने पूरी ताकत के साथ नही उठाये। ऐसे में तो सरकार को तो कुछ फर्क ही नही पड़ेगा।

21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के विषय में अखाड़ा न बने संसद

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को गर्माए रखने के लिए कांग्रेस समेत लगभग समूचे विपक्ष ने अपने-अपने हथियार भांज लिए हैं। यह आशंका कायम है कि विपक्षी दल संसद को ठप बनाए रखने में ही अपना समय जाया करेंगे। इस सत्र में लंबे समय तक चलने वाला हंगामा बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण को लेकर हो सकता है। चुनाव आयोग की इस बड़े प्रयास पर समूचा विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुटा है। लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बैठक भी की है। इस हंगामें में मुख्य रूप से कांग्रेस, राजद और तृणमूल कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। अतएव आशंका है कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर संसद में गतिरोध बनाए रखने की कोशिश युद्धस्तर पर होगी। सत्ता पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि निर्वाचन आयोग के बिहार की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अतएव विपक्ष इस मुद्दे के न्यायालय में विचाराधीन होने के बहाने को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करेगी।

सरकार ने इस सत्र में 08 नए विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए हैं। इन विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक- 2025, सार्वजनिक न्यास प्रणाली (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक- 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक- 2025, पुरातत्व धरोहर स्थल और अवशेष (संरक्षण और देखरेख विधेयक- 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक- 2025 एवं राष्ट्रीय डोपिंग (कचरा) रोधी संशोधन विधेयक- 2025 शामिल हैं। इन विधेयकों पर सहमति बनाए जाने की चर्चा से पहले विपक्ष चाहेगा कि पहलगाम हमले में गुप्तचर तंत्र की नाकामी, सैन्य अभिशन सिंदूर के दौरान विदेशी हस्तक्षेप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावों के बीच सेना के अभियान को अचानक क्यों रोका गया जैसे मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। विपक्ष की मंशा, मुद्दों की सच्चाई से कहीं ज्यादा सरकार को घेरना है। सत्तारूढ़ पक्ष इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बताकर चर्चा से बचने की कोशिश कर सकता है? इन बड़े मुद्दों के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के निवास में लगी आग के दौरान नकद धनराशि जलने के मामले में महाअभियोग लाने की पैरवी करने के साथ ओडीसा की छात्रा के साथ हुए अत्याचार जैसे मुद्दे भी सदन में गरमा सकते हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में सरकार को उम्मीद है कि यदि वह इस मुद्दे पर महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव लाती है तो उसे सभी दलों का समर्थन मिल सकता है। संभव है इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले वर्मा इस्तीफा दे दें। यदि नहीं देते हैं तो संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस संभव है। जिससे सत्तारूढ़ दल से कहीं ज्यादा न्यायिक साख प्रभावित होगी। यदि बहस होती है तो न्यायाधीशों की मनमानी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गहन विमर्श होना तय है।

कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मतदाता सूची को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जबकि सत्तारूढ़ दल चुनाव आयोग की जानकारी के आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बावजूद तेलगु देशम पार्टी द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जाने से सरकार की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। इधर निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ऐसा बयान आया है, जिसे सरकार अपनी ढाल बनाने का काम करेगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार में एसआइआर के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने के प्रयास में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने में आई है। बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से महज 6.85 प्रतिशत मतदाताओं ने अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना फार्म नहीं भरे हैं। यानी आयोग ने अंतिम तिथि से 9 दिन पहले ही 93 फीसदी काम पूरा कर लिया है। बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 6 करोड़ 99 लाख 92 हजार 926 मतदाताओं ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली मसविदा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपने गणना फार्म भर दिए है। हालांकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने इस कवायद पर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिन पर संसद में गरमा-गरम बहस हो सकती है। दरअसल समूचा विपक्ष इसलिए चिंतित है, क्योंकि पहली बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने की आधीकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है। यही वह समय है, जब राज्यों में सत्तारुढ़ भाजपा सरकारें घुसपैठियों को देश से विस्थापित करने के राष्ट्रहितैषी काम में लगी हैं।

इस बाबत असम के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ठीक ही कहा है कि असम जैसे राज्य में घुसपैठिए एक ही धर्म के लोग हैं, जो कांग्रेस समेत गैर भाजपा दलों को वोट करते हैं। इन घुसपैठियों को बाहर कर देने से ये दल हार के खतरे को अनुभव कर रहे हैं। जबकि घुसपैठिए कई राज्यों का जनसांख्यिकी घनत्व बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पुनरीक्षण में यह बात सामने आई है कि असम के सीमाक्वर्ती जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 15 लाख से अधिक हो सकती है। गृह विभाग ने भी कई जिलों में बांग्लादेशियों की संख्या को लेकर रिपोर्ट पेश की है। इसके अनुसार सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण कई जिलों का जनसांख्यिकी गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां चार प्रतिशत बढ़ी है, वहीं सीमाक्वर्ती जिलों में यह आंकड़ा करीब 16 प्रतिशत है। सरकारी दस्तावेजों में ये लोग भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं। इस कारण उन्हें अनेक केंद्र एवं राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस कारण उनका भारत की जमीन पर रहना आसान हो गया है।

अतएव प्रस्तावित विधेयकों की बजाय मतदाता सूची पर ज्यादा हंगामा होना तय है। यदि संसद में राजनीतिक गतिरोध बना रहता है और संसद अखाड़े में तब्दील होती रही तो उन विधेयकों और अधिनियमों पर बारीकी से बहस संभव नहीं है, जो देश की 1.4 करोड़ जनता की भलाई व नियमन के लिए कानून बनने जा रहे हैं ? प्रत्येक सांसद का दायित्व बनता है कि वह विधेयकों के प्रारूप का गंभीरता से अध्ययन करे, जिससे यह समझा जा सके कि उसमें शामिल प्रस्ताव देश व जनता के हित से जुड़े हैं अथवा नहीं? लेकिन राज्यसभा और लोकसभा का यह दुर्भाग्य है कि ज्यादातर सांसद अधिनियम के प्रारूप पर चर्चा करने की बजाय, ऐसे मुद्दों को बेवजह बीच में घसीट लाते हैं, जिनसे उनकी क्षेत्रीय राजनीति चमकती रहे। ऐसी स्थिति सत्तारुढ़ सरकार के लिए लाभदायी होती है, क्योंकि वह बिना किसी बहस-मुबाहिसे के ही ज्यादातर विधेयक पारित करा लेती है। जबकि विपक्ष सार्थक बहस करने की बजाय गाहे-बगाहे सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगा रहकर संसद का समय जाया कर देता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दृष्टि से यह स्थित देशहित में कतई नहीं है। इस लिहाज से सत्तारूढ़ सरकार और दल का कर्तव्य बनता है कि वह राजनीतिक गतिरोध का समाधान, राजनीतिक तौर-तरीकों से ही निकाले।

राज्य में डेढ़ वर्ष में बलात्कार के 2682 मामले दर्ज, वहीं छेड़छाड़ की 5174 घटनाएं सामने आईं

(पेज 1 का शेष)

लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमराई नजर आ रही है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में निरंतर वृद्धि ने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी संगठनों ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लूट, चैन स्नेचिंग और चोरी की बढ़ती वारदातों से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और पुलिस-प्रशासन अपराध रोकने में असफल साबित हो रहा है।

पुलिस महकमे में असंतोष और मनोबल गिरा

सिर्फ जनता ही नहीं, पुलिस महकमे के भीतर भी भारी असंतोष है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टिंग और ट्रांसफर में लगातार हस्तक्षेप से कर्मठ अफसर हतोत्साहित हैं। अपराध नियंत्रण, गश्त और खुफिया तंत्र मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि गृहमंत्री का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बल्कि राजनीतिक मैनेजमेंट और व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने पर रहा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुप्पी क्यों?

राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आखिर कब तक इस बदहाल स्थिति पर चुप्पी साधे रहेंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री खुद भी गृहमंत्री के कार्य से असंतुष्ट हैं लेकिन राजनीतिक संतुलन साधने के लिए उन्होंने अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया। विपक्ष का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं। गृहमंत्री पूरी तरह नाकाम हैं।

सत्ता पक्ष भी सख्त, दबाव में गृहमंत्री

सूत्रों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी गृहमंत्री विजय शर्मा को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अपराध नियंत्रण में सुधार नहीं आया तो उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। विधानसभा सत्र में विपक्ष गृहमंत्री पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी लगातार बढ़ते अपराध ग्राफ से चिंतित हैं।

गृहमंत्री का नहीं है कोई नियंत्रण

राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा का खुद कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि अपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह वे घटनाएं हैं जिनके बारे में विचार करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

बिहार-यूपी जैसे हालात बनते जा रहे हैं

छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बिहार, यूपी से भी ज्यादा डरावनी हो गयी है। गृहमंत्री विजय शर्मा राज्य को मणिपुर की तरह जलते हुये देखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश में पहली बार जातीय आधार पर संघर्ष होता देखा गया। राजधानी के सकरी गांव में दंगा हो गया, एक घर में आग लगा दी गई, वाहनों को जला दिया गया, यदि परिवार वाले गांव छोड़कर नहीं जाते तो 11 सदस्य का पूरा परिवार घर में जिंदा जल गया होता।

गृहमंत्री बनते ही दो महीने में हुए 54 नक्सली हमले

विजय शर्मा के गृहमंत्री बनने के बाद राज्य में एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य में 54 नक्सली घटनाएं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबल के सात जवान तथा एक 'गोपनीय सैनिक' शहीद हुआ है। इस दौरान 53 जवान घायल हुए तथा आठ नक्सली भी मारे गए हैं। नक्सली घटनाओं में सुकमा जिले में चार जवान शहीद हुए हैं तथा 25 जवान घायल हुए हैं। वहीं बीजापुर जिले में दो जवान शहीद हुए हैं तथा 21 जवान घायल हुए हैं। जिले में मुठभेड़ में चार नक्सली भी मारे गए हैं।

समुद्र के लिए आफत बनता प्लास्टिक

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

समुद्र, जो हमारे ग्रह का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा है, जीवन की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय स्रोत है। लेकिन आज समुद्र एक नए संकट का सामना कर रहा है और वह संकट है प्लास्टिक प्रदूषण। यह समस्या न केवल समुद्री जीवन के लिए खतरनाक है बल्कि मानव स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए भी एक खतरा है। यदि बड़ी संख्या में प्लास्टिक के टुकड़े समुद्र में तैर रहे हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब समुद्र पानी का नहीं बल्कि प्लास्टिक का ही कहलाएगा। दुनिया में आज 40 प्रतिशत समुद्र किसी न किसी तरह से प्लास्टिक के चपेट में आ चुका है और माना जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रहा तो 2050 तक मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में होगा। समुद्र में प्लास्टिक से फैलता संकट आज मानवता और प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ जहां एक ओर जीवन सुविधाजनक हुआ, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग और बेतरतीब निपटान ने प्रकृति के सामने एक भीषण संकट खड़ा कर दिया। समुद्री सतहों, तटों और गहराइयों में जमा यह प्लास्टिक केवल समुद्री जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाश का कारण बन चुका है।

हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों व नालों से होते हुए समुद्रों तक पहुँचता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 192 देशों से निकला करीब 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है जो हर मिनट एक ट्रक प्लास्टिक के बराबर है। अंतराष्ट्रीय शोधों ने भी पुष्टि की है कि समुद्रों में पहुंचने वाला करीब 80 फीसदी कचरा जमीन पर ठोस कचरे के कुप्रबंधन से जुड़ा है, जो भूमि से जुड़े समुद्री मार्गों के जरिए समुद्र तल तक पहुंच रहा है। वहीं बाकी 20 फीसदी कचरा तटीय बस्तियों से समुद्रों में जा रहा है।

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं- जैसे प्लेटें, बोतलें, बैग, फिशिंग नेट्स जो उपयोग होने के बाद बिना किसी रोकटोक के समंदर तक पहुँच जाती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाली प्रजातियां, जैसे- कछुए, सील, मछलियां व पक्षी, अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझ कर निगल जाती हैं। नतीजा, प्लास्टिक उनके पेट में जमता जाता है और वे भूख या बीमारी के कारण तड़प-तड़प कर मर जाती हैं। प्लास्टिक से बने माइक्रोप्लास्टिक कण एक और बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये कण इतने छोटे आकार के होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन समुद्री जीव इनका आसानी से सेवन कर लेते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो ये माइक्रोप्लास्टिक अब समुद्री जैव-श्रृंखला के जरिये इंसानी खुराक तक भी पहुँचने लगे हैं, जो धीरे-धीरे हमारी सेहत पर भी गंभीर असर डालता है- कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, और जन्मजात विकार इसके कुछ उदाहरण हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्लास्टिक की उम्र हजारों साल होती है, यानी एक बार समुद्र में गया प्लास्टिक कभी – न कभी – समुद्री जीवन के लिए खतरा बन ही जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ जंतुओं व मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह असंतुलित कर रहा है। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे डेड जोन यानी निर्जीव क्षेत्र बन जाते हैं, जहाँ कोई भी जीवित प्राणी बच नहीं पाता। रिक्त स्थानों में जब ऑक्सिजन नहीं मिलती, तो पूरी खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ जाती है। प्लास्टिक कचरे को जलाने या लंबे समय तक सूर्य के ताप के नीचे रहने की स्थिति में, इसमें मौजूद रसायन व विषैले तत्व समुंदर के पानी में घुल जाते हैं, जिससे और अधिक विषाक्तता फैलती है। एक और चिंताजनक पहलू है "प्लास्टिक की चट्टानों" (Plastiglomerates) का बनना, जैसा कि हाल में भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर देखा गया।

ये चट्टानें प्लास्टिक और रेत के मेल से बनती हैं, जिनमें सैकड़ों खतरनाक रसायन होते हैं। शोधों के अनुसार, समुद्र की गहराइयों में अब लगभग एक करोड़ दस लाख टन प्लास्टिक जमा हो चुका है। इस संकट का समाधान सरल नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग बंद करें, सिंगल-यूज प्लास्टिक के विकल्प चुनें, और प्लास्टिक कचरे के जिम्मेदार निस्तारण का प्रण लें। सरकार व समाज को मिलकर कानून और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के ठोस प्रयास करने होंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश के प्रयास काफी नहीं, पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस महासंकट का हल ढूंढना होगा। समुद्र हमारे पृथ्वी का फेफड़ा हैं। अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति स्वयं हमसे ऐसी कीमत चुकाएगी जिसकी भरपाई कभी न हो पाएगी। क्या आप भी प्लास्टिक मुक्त समुद्र की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे?

सनातन धर्म का पांच दिवसीय अनुष्ठान संपन्न

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। दिनांक 13 से 17 जुलाई 2025 तक नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में सनातन धर्म का अनुष्ठान किया गया। पंडित श्रीगणेश बिल्लौरे ने बताया कि वैसे तो हर दिन, हर समय मनुष्य को शुभ कर्म करते रहना चाहिए, इससे कल्याण होता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ विशेष मुहूर्त समय पर किए हुए शुभ कार्यों का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। कुछ दिन और समय विशेष कार्य के लिए उत्तम साबित होते हैं। जिनमें 13 जुलाई से 17 जुलाई के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 तक पवित्र सावन माह कृष्ण पक्ष में विशेष रहे। उक्त दिनों में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर महामृत्युंजय के जाप पंच ब्राह्मण के साथ पूजा उपासना अनुष्ठान किए गए जो सनातन धर्म के मानने वालों के लिए विशेष प्रभावकारी साबित होंगे और उससे पूरे जगत का कल्याण होना निश्चित है। पंडित श्रीगणेश बिल्लौरे ने सनातन धर्म को मानने वालों से आग्रह किया कि श्री हनुमान जी से सभी के कल्याण की मंगल कामना करें।

घोषणाओं के बीते 20 माह धरातल पर कार्य नदारद, कैसे होगा आदर्श विधानसभा का सपना पूरा

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। देश की आजादी के बाद पहली बार गाडरवारा विधानसभा से कोई विधायक मंत्री पद तक पहुंच सका। मंत्री उदय प्रताप राव इस क्षेत्र को लोगों को भी उनसे बड़ी आशा थी और उन्होंने उसी आशा के अनुरूप आदर्श विधानसभा का संकल्प लेते हुए गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगातें स्वीकृत कराकर अपने विधानसभा क्षेत्र में दी। परंतु घोषणाओं को 20 माह होने के बावजूद भी सैकड़ो करोड़ों रुपए के स्वीकृत कार्यों के बावजूद भी धरातल पर विकास कार्य कोसों दूर है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरे गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बढ़िया रोड गाडरवारा से गोटोटोनिया मार्ग है, परंतु मात्र 100 मीटर रोड रेलवे फाटक के पास जहां से एनटीपीसी के सैकड़ों ट्रक रोजाना निकलते हैं, परंतु वह आज तक नहीं बन पाई। गाडरवारा में बनने वाला फ्लाईओवर लगभग 7 साल से बन रहा है, जिसे मंत्री ने खुद स्वीकृत कराया था। परंतु आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। गाडरवारा में शनि मंदिर का फीडर जिसके लिए विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सुधार के लिए परमिट लिया जाता है। मार्च 2024 में 67 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी क्षेत्र में पांच रोड स्वीकृत की थी। प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत 55 करोड़ रुपए इस रोड में स्वीकृत हुआ था, लगभग 12 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कराया था। इसके टेंडर भी हो चुके थे, नवंबर 2024 में ठेकेदार द्वारा उसे ले भी लिया था, परंतु आज तक वर्क आदेश नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3000 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हैं। परंतु इसके बावजूद भी लगभग 1 साल होने जा रहा है। आखिर यह वन विभाग की परमिशन क्यों नहीं मिल रही।

एक ही मंदिर में लगातार तीसरी बार चोरी कभी नन्दी महराज चोरी होते हे तो कभी माता का जेवर

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी नगर के बीचों बीच स्थित भगवान भोलेनाथ का मंदिर जहां जो कि शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। 500 साल पुराना मंदिर माता सिंहवाहिनी भी विराजमान है। चोरों ने माता के जेवर के साथ दानपेटी की भी चोरी कर ली। यहां हम आपको बता दें लगातार इस मंदिर के तीसरी बार चोरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी संतोष पांडे जब्बा दिन की तरह जब सुबह मंदिर गए तो उन्होंने मंदिर के ताले टूटे देखे और दानपेटी खाली देखी और माता के जेवर चोरी देखे। थाना देवरी द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवरी नगर के लोगों में एक भय का माहौल है जब भगवान के मंदिर में चोरी लगातर हो रही है तो आम घर के चोरी होना तो आम बात है।

कलेक्टर की नजर मूंदी, पटवारी की चांदी- कन्नौद में प्रशासनिक बेईमानी का खुला खेल

-चंचल भारती

जगत प्रवाह. देवास। कन्नौद में पटवारी महेश मौर्य के घपलों ने तहसीलदार, SDM और कलेक्टर की साख धूल में मिला दी है। वारिसी जानकारी छुपाना, फर्जी कागजात, जमीन पर मंडराती दलाली- इन सबके सामने प्रशासन बस खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। पुराने SDM चुप्पी साधे रहे, नए SDM के.एल. तिलवारे ने सिर्फ सस्पेंड का झुनझुना दिया, न FIR, न कड़ी कार्रवाई! कलेक्टर दफ्तर भी गहरी नींद में, पूरे जिले में भ्रष्टाचार का वायरस फैल चुका- जनता का भरोसा बुरी तरह हिल गया है।

लोग अब पूछ रहे हैं: क्या सिर्फ सस्पेंड कर जनता को दोखा दिया जाता रहेगा, या वाकई दोषियों को जेल भेजने का साहस दिखाएगा प्रशासन?

औद्योगिक नीति

अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

- **स्थानीय युवाओं** को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान
- **आधुनिक खेती** से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा
- **वस्त्र क्षेत्र में निवेश** पर अब 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन
- **ग्लोबल कैपेबिलिटी** सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज
- **पर्यटन और होटल** व्यवसाय को बढ़ावा
- **नीति में संशोधन** से युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ

R.O. No. : 13331/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)